चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी)

डॉ. ध्रुबज्योति भट्टाचार्जी*

दक्षिण एशिया की पहचान एक ऐसे क्षेत्र के रूप में की जाती है, जो अस्थिर, आर्थिक रूप से अल्पविकसित और संघर्ष से ग्रस्त है। जब विकास के लिए सहयोग के अवसरों की मांग उठती है, तो स्वाभाविक रूप से इससे एक सुदृढ़तर तथा स्थिर क्षेत्र की संभावनाएं प्रबल होती हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के हाल के पाकिस्तान दौरे ने आने वाले वर्षों में पाकिस्तान के लिए ऐसी ही स्थिरता की संभावनाएं जगाई हैं। चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) को विकसित करने के जिस विचार की परिकल्पना चीनी प्रधानमंत्री ली केकियांग ने मई 2013 में अपनी पाकिस्तान यात्रा के दौरान की थी, उस विचार ने वर्तमान दौरे में एक समुचित आकार ग्रहण कर लिया है।[1] प्रस्तावित आर्थिक गलियारा पश्चिमोत्तर चीनी प्रांत झिंजियांग को लगभग 3000 किलोमीटर (1800 मील) लम्बे सड़क नेटवर्क के माध्यम से पाकिस्तानी पत्तन ग्वाधर से जोड़ेगा, जो पाकिस्तान को बहुप्रतीक्षित आर्थिक अवसंरचना, विशेषकर विद्युत-उत्पादन संयंत्र उपलब्ध कराएगा।[2]

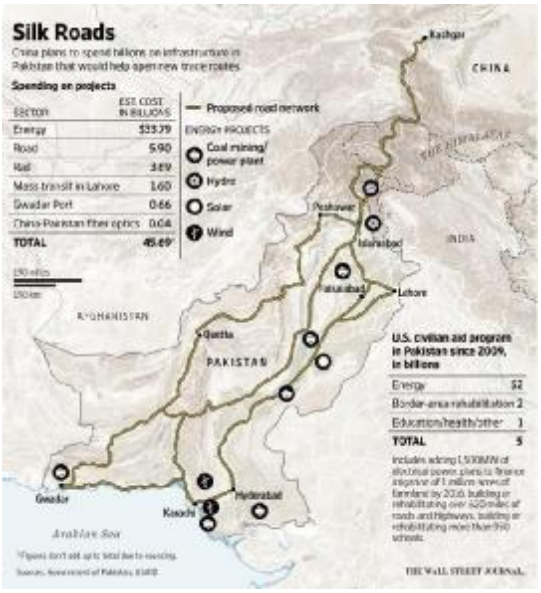

चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा वहां (उस क्षेत्र में) अवस्थित है, जहां रेशम मार्ग आर्थिक पट्टी (बेल्ट) और 21वीं शताब्दी समुद्री रेशम मार्ग आपस में मिलते हैं। इसलिए यह "पट्टी (बेल्ट) और सड़क" पहल की एक प्रमुख परियोजना है।[3]

बीजिंग की चिंता यह है कि आर्थिक विकास और स्थिरता के अभाव में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के कारण चीन के पश्चिमोत्तर भू-भाग में सुरक्षा कमजोर पड़ जाएगी। आर्थिक गलियारे का उद्देश्य किसी भी चीनी समुद्रतटीय पत्तन की तुलना में ज्यादा निकट अवस्थित निकास मार्ग ग्वाधर से इस गलियारे को जोड़कर चीन के मुस्लिम बहुल पश्चिमोत्तर क्षेत्र के आर्थिक विकास में सहायता करना है।[4]

चीन ने विकास सौदों में लगभग 46 अरब डॉलर उपलब्ध कराने का वायदा किया है, जो पाकिस्तान के वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 20 प्रतिशत के बराबर है।[5] कुल मिलाकर, इस आर्थिक गलियारा परियोजना का उद्देश्य लगभग 34 अरब डॉलर की लागत से लगभग 17000 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन करना है। शेष धनराशि परिवहन अवसंरचना पर खर्च की जाएगी, जिसमें कराची पत्तन मेगासिटी और पश्चिमोत्तर पेशावर शहर के बीच रेल मार्ग का उन्नयन शामिल है।[6]

इस योजना में सभी परियोजनाओं को वर्ष 2030 तक पूरा करने का आह्वान किया गया है।[7] यह आर्थिक गलियारा मध्य पूर्व से चीन के ऊर्जा आयातों के मार्ग को लगभग 12,000 किलोमीटर कम करने के साथ-साथ सड़क, रेल, व्यापार क्षेत्र, ऊर्जा योजनाओं और पाइपलाइनों के विशाल तथा जटिल नेटवर्क के जरिए पाक अधिकृत कश्मीर होते हुए अरब सागर पर चीन के अल्प-विकसित सुदूर पश्चिमी क्षेत्र को पाकिस्तान के ग्वाधर महासागर पत्तन से जोड़ेगा।[8] वर्ष 2017 तक लगभग 15.5 अरब डॉलर मूल्य की कोयला, पवन, सौर और जलविद्युत ऊर्जा परियोजनाएं कार्यान्वित हो जाएंगी और पाकिस्तान के राष्ट्रीय ग्रिड में 10,400 मेगावाट ऊर्जा की बढ़ोत्तरी करेंगी। दोनों देशों के बीच 4 करोड़ 40 लाख डॉलर मूल्य के ऑप्टिकल फाइबर केबल का निर्माण कार्य भी अपेक्षित है।[9]

चूंकि कुछ परियोजनाओं में पाक अधिकृत कश्मीर के विवादित क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले हिस्से भी शामिल होंगे, इसलिए भारत को इस गलियारे के संबंध में कुछ संदेह होता रहा है। हालांकि, सहायक विदेश मंत्री लिउ जियांचाओ ने मीडिया को दिए अपने वक्तव्य में इसे स्पष्ट किया, जब उन्होंने कहा, "चीन और पाकिस्तान के बीच की परियोजना का भारत-पाकिस्तान के बीच प्रासंगिक विवाद से कोई सरोकार नहीं है। इसलिए मैं नहीं समझता कि भारतीय पक्ष को इसके बारे में अधिक चिंता करनी चाहिए।"[10] फिर भी भारत ने इस मुद्दे पर संदेह व्यक्त किए हैं। जब भारत ने दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में तेल एवं गैस की खोज प्रारंभ की तब चीन ने इसे अपने "प्रमुख क्षेत्रों" में से एक घोषित कर दिया था।

चीन की निवेश नीति

एशिया के संबंध में चीन की नीतियों का विस्तार समुद्रीय मुद्दों पर दावेदारी दिखाने से लेकर प्रशांत क्षेत्र में युद्ध-पश्चात व्यवस्था को चुनौती देने, व्यापार सुदृढ़ता से निर्मित लाभकारी आर्थिक संबंधों के ताने-बाने को चलाने तक है, जो चीन को क्षेत्रीय एकीकरण का केन्द्र बना सकता है।[11] अक्तूबर 2013 में बाली में एपेक शिखर सम्मेलन में एक नए "समुद्री रेशम मार्ग" को परिभाषित करने वाले शी जिनपिंग के भाषण ने इस नेता की सोच स्पष्ट कर दी और अटकलों की संभावनाओं को समाप्त कर दिया।[12] विश्लेषकों ने स्पष्ट किया है कि वर्ष 2002 के बाद से चीन की विदेश नीति डेंग जियाओ पिंग के काल से जो भी निर्धारक अपने साथ लेकर आई और हू जिनताओ द्वारा लाए गए परिवर्तनों के साथ उसे जोड़ते हुए अमरीका के इर्द-गिर्द केन्द्रित है, जिसमें कुछ विश्लेषक अमरीका को एक 'दैवी समाधान' (deus ex machina)[13] मानते हैं, जिसकी अलग से जांच होनी चाहिए और दूसरे (विश्लेषक) इसे वैश्वीकरण तथा अंतर्राष्ट्रीय परस्पर-निर्भरता के अधिक उदार संदर्भ में देखते हैं।[14] चीन के लिए, विदेश नीति का स्थान आंतरिक स्थिरता और आर्थिक वृद्धि बनाए रखने के घरेलू लक्ष्यों के बाद आता है।[15]

वर्ष 2001 में चीन की "गो ग्लोबल" पहल के कार्यान्वयन के बाद चीनी सरकार ने अपने विदेशी विनिमय नियंत्रणों, अनुमोदन प्रक्रियाओं और निवेश प्रतिबंधों में छूट दे दी है। वर्ष 2003 के बाद से निजी स्वामित्व वाले उद्यमों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेश करने की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन देने की अनुमति दे दी गई है।[16] इस समय से चीन का प्रत्यक्ष बाह्य निवेश (ओडीआई), जो वर्ष 2003 में तीन खरब अमरीकी डॉलर से भी कम था, तेज गति से बढ़ा है और यह वर्ष 2011 में बढ़कर 70 अरब अमरीकी डॉलर से भी अधिक हो गया है।[17] जहां सरकारी स्वामित्व वाले उद्यम - विशेषकर पेट्रॉलियम, निर्माण, दूर संचार और नौवहन - सबसे बड़े निवेशक बने हुए हैं, वहीं लेनोवो जैसी निजी कंपनियों ने विदेशों में निवेश करना प्रारंभ कर दिया है।[18]

हालांकि चीन का अधिकांश प्रत्यक्ष बाह्य निवेश (ओडीआई) दक्षिण पूर्व एशिया की दिशा में है; लेकिन वर्ष 2003 के बाद से चीन ने दक्षिण एशिया में अपने राजनयिक तथा आर्थिक कार्यकलाप (फोकस) बढ़ा दिए हैं। यह पता लगाना कठिन है कि क्या चीन द्वारा दक्षिण एशिया के साथ अपने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के पीछे भू-राजनैतिक कारण हैं। एक ओर, चीन का उद्देश्य केवल निर्यात-आधारित विकास कार्यनीतियों का कार्यान्वयन और व्यापार मार्गों के विस्तार की इच्छा हो सकता है। दूसरी ओर, चीन के लिए इस क्षेत्र के साथ संबंध राजनयिक दबावों का प्रयोग करने और अपनी सेना की पहुंच/दायरे के विस्तार के लिए भी समान रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है।[19] इस प्रकार की धमकियों को नज़रअंदाज किया जा सकता था, यदि चीनी सेना, विशेषकर जनवादी सशस्त्र बल, भारत में सीमा का अतिक्रमण करते समय संयम दिखाते।[20] भारत को रक्षात्मक बनाए रखने के लिए चीन सीमा पर घुसपैठ की कार्रवाई

बार-बार करता रहा है। प्रत्येक बड़े द्विपक्षीय दौरे से पहले ऐसे घुसपैठ गंभीर रूप/आयाम धारण करने लगते हैं।[21] चीन ने हाल के अपने नीति निर्धारणों में विवादों के समाधान पर जोर नहीं दिया है और उसने यह अनकहा वक्तव्य दिया है कि पड़ोसी अपनी आकांक्षाओं तथा दावों की रूपरेखा कम करके प्रतिक्रिया देने के लिए होते हैं।[22]

विभिन्न विश्लेषकों ने चीनी सहायता तथा (चीनी) विदेशी परियोजनाओं में काम-काज़ के तरीकों का मूल्यांकन करने का प्रयास किया है, क्योंकि ऐसे विवरण चीनियों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार पारदर्शी नहीं हैं। चीन द्वारा वर्ष 2011 में जारी किये गए श्वेत-पत्र के अनुसार यह उल्लेख किया गया था कि चीन प्राप्तकर्ता देशों को उनकी आत्म-विकास क्षमता सुदृढ़ करने, अपने लोगों की आजीविका समृद्ध एवं उन्नत बनाने और उनकी आर्थिक वृद्धि तथा सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने में सहायता देगा। वर्ष 2011 के श्वेत पत्र का उद्देश्य चीन की विदेश सहायता नीति तय करना और चीन के विदेश सहायता तंत्रों के बारे में सूचना प्रदान करना था। वर्ष 2011 के श्वेत-पत्र के विस्तार के रूप में, श्वेत-पत्र-2 वर्ष 2010 और 2012 के बीच चीन की विदेश सहायता का पर्यावलोकन प्रस्तुत करता है और इन्हीं तीन वर्षों की अवधि के दौरान इस संबंध में चीन की उपलब्धियों का वर्णन करता है। उपलब्ध कराए गए आंकड़ों एवं सांख्यिकी में वाणिज्य मंत्रालय (एमओएफसीओएम) के सहायता आंकड़े तथा एक्जिम बैंक से प्राप्त रियायती ऋणों को शामिल किया गया है और अन्य मंत्रालयों से प्राप्त सरकारी सहायता को शामिल नहीं किया गया है (इसमें वित्त मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय द्वारा विश्व बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसियों को दिये गए अंशदान भी शामिल नहीं हैं)।[23] ये अनुदान, जो कभी-कभार गुप्त अनुदान होते हैं, मूलत: चीन के उत्थान के संबंध में सकारात्मक क्षेत्र विकसित करने और चीनी श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए होते हैं।

चीनी दृष्टिकोण

चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) में भारी निवेश करके चीन ने अपने बहुविद हितों को पूरा करने का प्रयास किया है। लगभग 45.6 अरब डॉलर की ऊर्जा और अवसंरचनात्मक परियोजनाएं अगले छह वर्षों के दौरान पूरी कर ली जाएंगी और तब चीनी कम्पनियां इन परियोजनाओं को लाभ कमाने वाले प्रतिष्ठानों के रूप में चलाने में समर्थ होंगी। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, चीनी राष्ट्र और इसके बैंक इस कार्य को पूरा करने के लिए चीनी कम्पनियों को उधार देकर इसे वाणिज्यिक उद्यम बनाएंगे, जिससे चीन की मंद होती अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा (सकारात्मक) प्रभाव पड़ेगा ।[24]

हालांकि पाकिस्तान अनियंत्रित सरकारी भ्रष्टाचार, आतंकवाद, अलगाववाद और राजनीतिक उतार-चढ़ाव के लिए कुख्यात है, फिर भी चीन इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण वित्तीय निवेश करता रहा है। हालांकि, पाकिस्तानी क्षेत्र के भीतर चीनी नागरिकों अथवा अधिकारियों को लक्ष्य बनाए जाने की तीन ही बड़ी घटनाएं (एक बलूची विद्रोहियों द्वारा [2004] और दो पाकिस्तानी तालिबान द्वारा [2008 और 2014]) हुई हैं, फिर भी इस क्षेत्र में विकास कार्यों पर छिटपुट हादसे और आक्रमण होते रहे हैं। ग्वाधर पत्तन पर ऐसा ही एक आक्रमण, जिसका बलूची विद्रोहियों ने विरोध किया, चीनी राष्ट्रपति के दौरे के साथ ही समाप्त हुआ। इस विशिष्ट क्षेत्र को विकसित करने के पीछे एक विशिष्ट आतंकवादी विरोधी आयाम था। चीन को पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामी आंदोलन (ईटीआईएम) के कारण अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, जो पिछले दो वर्षों के दौरान सैकड़ों चीनी लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार था।[26] इस गलियारे के सीमा क्षेत्र में पड़ने वाले क्षेत्रों को विकसित करने से झिंजियांग में आतंकी आयाम सुलझ सकते हैं, जो अल्प-विकास और पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान की सीमाओं के नज़दीक उईघुर विद्रोहियों के प्रशिक्षण शिविर होने के कारण कुख्यात हैं। चीन अपने मुस्लिम बहुल पश्चिमोत्तर क्षेत्र झिंजियांग में जातीय उईघुर द्वारा की जाने वाली हिंसा से भी चिंतित है और उसे डर है कि कट्टर अलगावादी पाकिस्तान के तालिबान सदस्यों के साथ मिलकर लड़ने वाले उईघुर आतंकियों के साथ मिल सकते हैं।[27]

चूंकि चीन और पाकिस्तान दोनों ही सरकारों द्वारा खतरे की अवधारणा को वास्तविक पाया गया है, इसलिए पाकिस्तान-चीन आर्थिक परियोजनाओं की रक्षा के लिए पाकिस्तान एक विशेष सुरक्षा डिविजन उपलब्ध कराएगा जिसमें कटिबद्ध 12000 सैनिकों के सुदृढ़ सैन्य बटालियन और सीएएफ (सिविल आर्म्ड फोर्सेज) विंग होंगे । इस डिविजन का नेतृत्व एक मेजर जनरल करेंगे और यह नौ सैन्य बटालियनों और छह सीएएफ स्कंधों (रेंजर और फ्रंटियर कोर) से मिलकर बना होगा।[28] इस विशेष बल को आंशिक रूप से प्रशिक्षण पब्बी में हाल ही में स्थापित राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी केंद्र में दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण व्यवस्था में सुरक्षा, आतंकवाद विरोध और आसूचना अभ्यास शामिल होंगे।[29]

यह परियोजना चीन को हिन्द महासागर तथा उससे आगे के क्षेत्र में सीधा प्रवेश भी देती है, जो मध्य तथा दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने की चीन की योजनाओं में एक बड़ी प्रगति है।[30] विश्व के सबसे बड़े तेल आयातक होने के कारण, ऊर्जा सुरक्षा चीन के लिए प्रमुख चिंता है। इसका एक पाइपलाइन है जो वस्तुत: खाड़ी से चीन तक फैला हुआ है, जिससे दक्षिण-पूर्व एशिया से होते हुए समुद्र क्षेत्र में दूरी हजारों किलोमीटर कम हो गई है।[31]

नवम्बर 2014 में शी (जिनपिंग) ने विदेश मामलों से जुड़े कार्यों पर चीनी साम्यवादी दल के प्रमुख सम्मेलन में एक भाषण दिया। इस भाषण में राष्ट्रपति ने चीन के राजनयिक उद्देश्यों में कदाचित नई व्यवस्था प्रस्तुत की। उन्होंने अन्य प्रमुख शक्तियों के साथ संबंधों के प्रबंधन के स्थान पर पड़ोस कूटनीति को बढ़ावा देने पर जोर देने की बात कही, जो अमरीका के साथ बेहतर संबंध बनाने के संबंध में वर्ष 2012 में दिए उनके उस वक्तव्य से भिन्न था, जिसमें उन्होंने एक वाक्यांश गढ़ा, एक "नए प्रकार का महान शक्तियों का संबंध।" चीन को Thucydides के जाल में फंसने से बचना होगा: जो एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है, जिसमें एक उभरती ताकत, यहां चीन, एक स्थापित ताकत, यहां अमरीका, में डर पैदा करता है, जो अंततः खुले टकराव का रूप धारण कर लेती है।[32] वर्तमान महाशक्ति अमरीका और इसके घनिष्ठ सहयोगी जापान के साथ चीन के संबंध संरचनात्मक कारणों से एक निश्चित सीमा से ज्यादा नहीं सुधर सकते। इसलिए चीन को अपने प्रयास वहां केन्द्रित करने होंगे, जहां वे सर्वाधिक प्रभावकारी हो सकें: अर्थात इसे अपने पड़ोसियों के साथ अपने संबंध सुधारने के प्रयास करने होंगे। इस प्रकार, चीन के लिए अपने उत्थान को बनाए रखने की सर्वोतम रणनीति है – अपनी पड़ोस कूटनीति को विकसित करना। नई रेशम मार्ग परियोजनाएं इस उद्देश्य की प्राप्ति में प्रमुख होंगी।[33]

विश्लेषकों ने चीनी निर्णयकर्ताओं को "दोधारी तरीका" अपनाने के सुझाव दिए हैं, जिसमें विकसित बड़ी शक्तियों के साथ नए शक्तिशाली संबंध स्थापित करते समय इसे विकासशील तथा पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंधों को सुधारना चाहिए। इसमें लि योंग हुई, निर्देशक, अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्कूल, बीजिंग विदेश अध्ययन विश्वविद्यालय, के रूख की अनुकृति/प्रतिध्वनि है, जिन्होंने वर्ष 2013 के अंत में कहा था कि उभरती ताकतों को एक अनुकूल परिधि की आवश्यकता पड़ती है जिसे उन्होंने एक “रणनीतिक परिधि क्षेत्र” का नाम दिया।[34] चीन ने न केवल चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे में निवेश किया, बल्कि इसकी योजना "मध्य एशिया में रेशम मार्ग आर्थिक क्षेत्र," "दक्षिण पूर्व एशिया में समुद्री रेशम मार्ग", और "दक्षिण एशिया आर्थिक गलियारा", जो चीन को वर्मा, बांग्लादेश और भारत के साथ जोड़ेगा, में निवेश करने की भी है।

प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी बातचीत में चीनी प्रधानमंत्री लि केक्यांग ने बीजिंग द्वारा समर्थित अनेक पश्चिमोन्मुख आर्थिक योजनाओं में से एक, बांग्लादेश-चीन-भारत-म्यांमार (बीसीआईएम) आर्थिक गलियारे के विकास को जारी रखने में रूचि व्यक्त की। चीन भारत को भी पूर्वोतर एशिया, भारत और अफ्रीका के रास्ते चीन और यूरोप को जोड़ने वाले महत्वाकांक्षी समुद्री व्यापार मार्ग - "नए समुद्री रेशम मार्ग" का साझेदार बनाना चाहता है। पश्चिमी एशिया तथा उसके आगे के क्षेत्र के साथ आर्थिक एकीकरण के लिए थल तथा जल दोनों में ही भारत चीन

की नज़र में महत्वपूर्ण है। बीजिंग को आशा है कि भारत के लिए मोदी के आर्थिक लक्ष्यों के साथ इसका दृष्टिकोण अच्छी तरह घुल-मिल जाएगा।[35]

समुद्री रेशम मार्ग इन तीनों परियोजनाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मध्य एशिया में रेशम मार्ग आर्थिक क्षेत्र का उद्देश्य चीन के "रणनीतिक पृष्ठभाग" को एक ऐसे क्षेत्र में सुदृढ़ बनाना है, जहां आर्थिक विकास की क्षमता एवं परम्परागत सुरक्षा खतरे दोनों पहले से ही कम हैं। लेकिन समुद्री रेशम मार्ग चीन के अभ्युदय के मध्यवर्ती क्षेत्र से संबंध रखता है। यदि चीन को अमरीका के क्षेत्रीय प्रभाव का सामना करना है तो दक्षिण-पूर्व एशिया में निवेश तथा भागीदारी ज्यादा जरूरी है और यह मध्य एशिया की तुलना में ज्यादा रणनीतिक लाभ प्रदान करेगा।[36]

पाकिस्तानी संदर्भ

पाकिस्तान की प्रमुख उपलब्धि उस स्थानिक ऊर्जा संकट का त्वरित और स्थायी समाधान तलाश करने में चीन का सहयोग प्राप्त करना है, जिसने इसे जकड़ा हुआ है। प्रस्तावित परियोजना पाकिस्तान की जीर्ण-शीर्ण विद्युत अवसंरचना की समस्या दूर करने का प्रयास करेगी। यह एक अति आवश्यक तथा लंबे समय से अनसुलझी ऐसी समस्या है, जो, विशेषज्ञों के अनुसार, प्रत्येक वर्ष इस देश के सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम दो प्रतिशत काटती है (कम करती है)।[37] यह परियोजना कोयला, परमाणु और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से पाकिस्तान के ऊर्जा ग्रिड में 10,400 मेगावाट जोड़ेगी।[38]

पाकिस्तान और चीन ने 20 अप्रैल को पाकिस्तान–चीन आर्थिक गलियारे (पीसीईसी) के तहत 'शीघ्र उत्पाद' परियोजनाओं को तत्काल प्रारंभ करने के लिए 20 अरब अमरीकी डॉलर मूल्य के करारों पर हस्ताक्षर किये हैं। 28 अरब अमरीकी डॉलर वित्तपोषण करार तत्काल कार्यान्वयन चरण में प्रवेश कर जाऐंगे, क्योंकि आवश्यक प्रक्रियाएं पहले ही पूरी की जा चुकी हैं: पंजाब में 1000 मेगावाट सौर शक्ति पार्क; 870 मेगावाट सुकी कनारी "खैबर पख्तूनख्वा" जलविद्युत परियोजना; 720 मेगावाट कारोत (एजेके) जलविद्युत परियोजना; तीन पवन शक्ति परियोजनाएं, थट्टा में संयुक्त ऊर्जा पकिस्तान (100 मेगावाट) साचल (50 मेगावाट) हाईड्रोचाईना (50 मेगावाट); काराकोरम राजमार्ग (हवेलियन से थकोट तक) के द्वितीय चरण उन्नयन के लिए चीन सरकार के रियायती ऋण; कराची लाहौर मोटरमार्ग (मुलतान से सूक्कूर तक), ग्वाधर पत्तन पूर्वी-खाड़ी एक्सप्रेस-वे परियोजना और ग्वाधर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा; जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए सामग्री का प्रावधान; ग्वाधर पत्तन क्षेत्र में परियोजनाएं और चीन-पाकिस्तान संयुक्त कपास जैव-तकनीक प्रयोगशाला और चीन-पाकिस्तान संयुक्त समुद्री अनुसंधान केन्द्र।[39]

चीन के प्रेस, प्रकाशन, रेडियो, फिल्म और टेलीविजन राज्य प्रसारण और पाकिस्तान के सूचना प्रसारण तथा राष्ट्रीय विरासत मंत्रालय के बीच सहयोग के लिए एक करार और चीन सेन्ट्रल टेलीविजन तथा पीटीवी एवं पाकिस्तान टेलीवीजन फाउन्डेशन के बीच पाकिस्तान में सीसी टीवी- न्यूज/सीसी टीवी-9 वृत्तचित्र (डॉक्यूमेंट्री) के पुन: प्रसारण के लिए एक त्रिपक्षीय करार पर भी हस्ताक्षर किये गए।[40] चेंग्डू (चीन के सिचुआन प्रांत में) और लाहौर; झूहाई (ग्वांगडोंग प्रांत) तथा ग्वाधर और कारामे (झिनजियांग, उइघुर) और ग्वाधर के बीच सहयोगी शहर संबंध स्थापित करने पर भी प्रोटोकॉल करार हुए।[41]

ग्वाधर–नवाबशाह एलएनजी टर्मिनल तथा पाइपलाईन परियोजना और लाहौर ऑरेंज लाइन मेट्रो रेल परियोजना, पत्तन कासिम 2x660 मेगावाट (1320 मेगावाट) कोयला-चलित शक्ति संयंत्र, झिंपीर पवन शक्ति परियोजना, थार ब्लॉक–II 3.8 मिलियन टन कोयला उत्पादन प्रतिवर्ष और थार ब्लॉक–II 3x330 मेगावाट (660 मेगावाट) कोयला चलित शक्ति परियोजना के वित्तपोषण से संबंधित व्यावसायिक ठेका तथा करार के संबंध में एक और करार पर हस्ताक्षर किया गया।[42]

पाकिस्तान–चीन आर्थिक गलियारे (पीसीईसी) के कार्यान्वयन के लिए चीन विकास निगम और हबीब बैंक लिमिटेड द्वारा एक वित्तीय सहयोग करार पर हस्ताक्षर किया गया। वापदा, पीपीआईबी और चीन तीन घाटी निगम (सीटीजी) के बीच जलविद्युत परियोजनाओं के विकास पर और निजी जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए रेशम मार्ग कोष में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किये गए।[43]

दाऊद पवन शक्ति परियोजना के लिए चीनी औद्योगिक तथा वाणिज्यिक बैंक (आईसीबीपी), चीन के पीसीसी और एचडीपीपीएल के बीच एक वित्तपोषण सुविधा करार पर और पाकिस्तान में चीनी निवेशों के संवर्धन तथा औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए आईसीबीसी तथा एचबीएल के बीच वित्तीय सेवा सहयोग पर एक फ्रेमवर्क करार पर हस्ताक्षर किए गए।[44]

बलूचिस्तान एक ऐसा क्षेत्र रहा है जो पाकिस्तानी सरकार के लिए विवादास्पद रहा है और जो अनेक अतिवादी तथा अलगाववादी समूहों का गढ़ है। इस गलियारे का बड़ा हिस्सा उस क्षेत्र में पड़ेगा जो उस प्रान्त की जनसांख्यिकी को बदल देगा और इसे आर्थिक रूप से अधिक व्यवहार्य, स्थिर तथा संधारणीय बना देगा। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ ने भी कहा है कि यह गलियारा पाकिस्तान को आर्थिक कार्यकलापों के क्षेत्रीय केंद्र में बदल देगा।[45]

चीनी निवेश - शामिल चुनौतियां

Ø चीनी निवेशों की सफलता की दर और गुणवत्ता स्तर बनाए रखने के बारे में कई आशंकाएं भी रही हैं। चीनी राज्य एजेंसी से संबद्ध दो अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार, पूरी हो चुकी प्रमुख परियोजनाओं का वितरण दर, जो 1990 के दशक के अंत में 74-79 प्रतिशत था, अब गिरकर 60 प्रतिशत से कम रह गया है। इसका अर्थ यह है कि लगभग 40 प्रतिशत चीनी निवेश परियोजनाएं या तो समय पर पूरी नहीं हुईं या अधूरी रह गईं।[46]

इससे भी ज्यादा चेतावनी भरे आंकड़े, जिसने विश्व भर में सुर्खियां बटोरीं, यह बताते हैं कि प्रभावहीन निवेश के कारण चीन को वर्ष 1997 के बाद से 10.8 खरब अमरीकी डॉलर की लागत सहनी पड़ी है। बासठ प्रतिशत अर्थात 6.8 खरब अमरीकी डॉलर का फालतू निवश वर्ष 2009 के बाद किया गया, जब चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए खुलकर निवेश किया। चीनी सरकार और राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम अवसंरचना तथा कारखानों में प्रतिवर्ष 2.3 खरब अमरीकी डॉलर (देश के कुल निवेश का 43 प्रतिशत) निवेश करते हैं। चूंकि सरकार द्वारा वित्तपोषित निवेश राजनीतिक निर्णयों से प्रेरित होते हैं, इसलिए इन निवेशों के बेकार जाने तथा भ्रष्टाचार का शिकार बनने की संभावना अधिक रहती है।[47]

एडविन ली, एक वकील और विदेशी (ओवरसीज) निवेश सलाहकार ने *चाईना डायलॉग* से बातचीत करते हुए बताया, "वर्तमान में चीनी विदेशी निवेश का प्रमुख पहलू, जो मेजबान राष्ट्रों में घबराहट पैदा कर देता है, वह है, संसाधनों को प्राप्त करने पर बहुत ज्यादा ध्यान देना। मीडिया में रिपोर्ट किये गए मुद्दे – प्रदूषण, कमजोर सामुदायिक संबंध, स्थानीय श्रमिकों के उपयोग में विफलता - ये सभी चीनी कम्पनियों द्वारा अनुपयुक्त तरीके अपनाने के परिणाम हैं।"[48] उन्होंने कहा कि जब चीन विकसित विश्व जैसे अमरीका अथवा आस्ट्रेलिया में निवेश करता है, तो वह स्थानीय कानून संरचना का अनुपालन करने के महत्वपूर्ण प्रयास करता है तथा विशेषज्ञ कानूनी सलाहकार नियुक्त करता है, ताकि कोई भी स्थानीय कानून टूटने न पाए। लेकिन आम तौर पर इसका अनुपालन तब नहीं किया जाता जब चीन विकासशील विश्व में निवेश करता है। इसी प्रकार, चीन ने खाड़ी की ओर पहुंचने के मार्ग अथवा हिंद महासागर व्यापार मार्ग को या तो अत्यधिक विकसित किया है या विकसित करना चाहता है अथवा मेजबान देश के कच्चे माल तक अपनी पहुंच/संपर्क बढ़ाना चाहता है। यदि आपके पास कोई व्यवस्थित औद्योगिक श्रृंखला है तो आपकी कच्चे माल की आपूर्ति में कटौती का अर्थ यह होगा कि इसके प्रसंस्करण तथा विनिर्माण कार्यों में लगे कर्मचारियों का काम छूट जाएगा, जिसका अर्थ यह है कि सरकार अधिक सावधान रहेगी।[49]

एक वरिष्ठ विश्लेषक एवं राजनयिक के साथ एक चर्चा के अनुसार चीनी विदेशी निवेशों को जिस तरीके से उपयोग में लाया जाता है, वह वर्ष 2011 और 2014 में चीन द्वारा जारी श्वेतपत्रों के मूल विषय का गंभीर उल्लंघन करता है। विशेषकर पिछले तीन से चार दशकों में अफ्रीका सहित अपने पड़ोसी राष्ट्रों में चीन द्वारा किये गए व्यापक निवेशों में द्विपक्षीय निवेश सौदे प्राय: अपारदर्शी तरीके के रहे हैं। विभिन्न अवसंरचनात्मक विकास परियोजनाओं में स्थानीय देशी बाज़ारों की पूर्णत: अनदेखी की गई है तथा चीनी सेवाओं एवं संभारतंत्रों पर पूरा भार डाला गया है, जिसमें श्रमिक तक भी चीनी मुख्य भू-भाग से लाए जाते हैं, वेतन का भुगतान उनके परिवारों को सीधे ही कर दिया जाता है, श्रमिकों का भरण-पोषण सीधे चीन द्वारा दिया जाता है, सभी सामग्री और विनिर्माण सामग्री मुख्य भू-भाग से लाई जाती है, जिसका भुगतान निवेश पैकेज से किया जाता है। इस प्रकार से, हालांकि, ऐसा प्रतीत होता है कि एक विशाल निवेश किया गया है, फिर भी संपूर्ण विकासात्मक प्रक्रिया में एक भी युआन चीन से बाहर नहीं जाता।[50]

Ø चीन की तथाकथित नव-साम्राज्यवादी भूमिका की भी चर्चा विश्लेषकों द्वारा की गई है, जब चीन लैटिन अमेरिका, अफ्रीका के साथ-साथ अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान में भी सक्रिय/शामिल रहा है। वर्ष 2006 में, जब अफगान राष्ट्रपति करजई ने विदेशी निवेश के लिए अफगानिस्तान के विशाल खनिज भंडारों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों को खोल दिया तो चीन ने इस आर्थिक अप्रत्याशित आय का पूरा लाभ उठाया। जहां अमरीका तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहायता बल (आईएसएएफ) ने अफगानी जनता को सुरक्षा उपलब्ध कराया, वहीं चीनी आर्थिक साम्राज्यवाद स्थापित कर रहे थे। चीन ने 240 मिलियन टन अयस्क वाले विश्व के सबसे बड़े छिछले भण्डार होने की संभावना वाले लोगर प्रांत में अयंक तांबा क्षेत्र पर नियंत्रण करने के लिए अमरीका, कनाडा तथा रूस की कम्पनियों को षडयंत्रपूर्वक बाहर का रास्ता दिखलाया। चीन के धतुशोधन समूह निगम, अथवा एमसीसी ने 3.9 अरब अमरीकी डॉलर की बोली लगाकर अन्य कम्पनियों को बाहर का रास्ता दिखलाया लेकिन यह तो कहानी का केवल एक हिस्सा है।[51] पीआरसी, जो संयोगवश एमसीसी के 44 प्रतिशत का स्वामी है, ने चीनी कम्पनियों द्वारा लक्षित व्यापक विकास परियोजनाओं का ठेका सीधे ही प्राप्त करना चाहा ।[52] यह एक ऐसी प्रतियोगी सुविधा है जो अन्य देशों की कम्पनियों को प्राप्त नहीं है।[53] विश्लेषकों द्वारा भी कहा गया है कि पाकिस्तान में पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामी आन्दोलन को नियंत्रित करने के लिए, चीनी नेतृत्व ने इन आतंकवादियों के विरूद्ध सैन्य अभियानों को सहायता प्रदान करने के लिए एफएटीए में आधारभूत[54] अधिकारों की मांग की है। लेकिन वर्तमान करार के लागू रहने पर यह चीनी नेतृत्व को एक बड़ी सुनियोजित योजना की रूपरेखा बनाने में सहयोग देगा, जिसमें न केवल पाकिस्तान के मुख्य भूभाग से चलाई जाने वाली चीन-विरोधी गतिविधियों को नियंत्रित करना, बल्कि खाड़ी के साथ-साथ हिन्द महासागर में भी प्रवेश पाना

शामिल होगा, जिससे उन लोगों के तर्कों को भी बल मिलता है जो भारत की घेराबंदी संबंधी चीनी सिद्धांत के पक्षधर हैं।

- पाक अधिकृत कश्मीर, जो भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र रहा है, में चीन ने अत्यधिक निवेश किया है, विशेषकर काराकोरम राजमार्ग को विकसित करने में, जिसमें पिपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के निर्माण कोर से जुड़े कई हजार चीनी कार्मिक कार्यरत रहे हैं।[55] चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का एक बड़ा हिस्सा पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगिट-बाल्टिस्तान क्षेत्रों में पड़ता है, जिसका भारत के कुछ विश्लेषकों ने विरोध किया है।[56] चूंकि चीन अरूणाचल प्रदेश में किसी भी प्रकार के विकासात्मक कार्य का समर्थन नहीं करता और जैसा कि विश्लेषकों ने मुद्दा उठाया है कि चीन "अरूणाचल प्रदेश में विकासात्मक परियोजनाओं के लिए एशिया विकास बैंक द्वारा दी जा रही धनराशि के विरूद्ध रहा है, क्योंकि वह इसे विवादित क्षेत्र मानता है; बीजिंग ने अरूणाचल प्रदेश में ऐसी परियोजनाओं के लिए उपयोग में लाई जा रही जापानी धनराशि पर भी विरोध जताया है।[57] यह दर्शाता है कि जहां तक पाक अधिकृत कश्मीर और अरूणाचल प्रदेश के विवादित क्षेत्रों का प्रश्न है, चीन किस हद तक दोहरा रवैया अपनाता है। यहां तक कि चीन भारतीय प्रधानमंत्री के अरूणाचल प्रदेश दौरे का भी विरोध करता है, जो भारत का एक अभिन्न अंग है।[58]

भारत दक्षिण एशियाई राष्ट्रों के बीच अपनी स्थिति सुदृढ़ करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। प्रधानमंत्री के शपथग्रहण समारोह के दौरान सकारात्मक स्थिति निर्धारण; सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान काठमांडू में मोदी द्वारा निभाई गई भूमिका; नेतृत्व द्वारा बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका के किए गए अनेक दौरे; जापान तथा अमरीका के साथ निकटता; और चीन के साथ बारम्बार वार्ताएं तथा वहां के दौरे; इन सभी ने भारत की कूटनीतिक तथा क्षेत्रीय आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण आयाम जोड़े हैं। कुछ विश्लेषकों ने कहा है कि चीन द्वारा यथा-प्रस्तावित रेशम मार्ग का खुला समर्थन कुछ वैसे क्षेत्रों में भारत की संप्रभु स्थिति को जोखिम में डाल देगा, जिसे चीन अपना क्षेत्र होने का दावा करता है, विशेषकर अकसाई चीन क्षेत्र तथा अरूणाचल प्रदेश में। भारत ने जिन समान्तर परियोजनाओं को प्रारंभ किया है, उन्हें सुदृढ़ करने के लिए पूरे दमखम से कार्य करना चाहिए, जैसे उत्तर दक्षिण गलियारे के क्षेत्र में "कपास मार्ग" परियोजना के साथ-साथ मौसम परियोजना, जो अपने प्राचीन परम्परागत समुद्री मार्गों को पुन: खोलने और अपने विस्तारित पड़ोस के देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को पुन: बहाल करने की दिशा में एक क्षेत्रीय पहल है।[59] भारत को चाबहार पत्तन के विकास पर और अधिक जोर देना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के रास्ते पारगमन के अभाव में अफगानिस्तान, मध्य एशिया तथा रूस तथा इससे आगे जाने के लिए ईरान भारत का द्वार है और चाबहार पत्तन इसमें मुख्य भूमिका में है।[60] चाबहार को सुदृढ़ करने का कार्य उस असंतुलित

विकास प्रक्रिया के विरोध की दिशा में एक मजबूत पहल के रूप में कार्य करेगा, जो दक्षिण एशिया के नाजुक संतुलन को कमजोर कर सकता है। ऐसी परियोजनाओं को सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता है क्योंकि इससे सच्चे अर्थों में विकास कार्यकलाप को आधार मिलेगा न कि बड़ी ताकतों द्वारा संसाधनों का दोहन होगा, जिसके परिणामस्वरूप अनुदान तथा सहायता की आड़ में और अधिक नुकसान तथा शोषण होता है।

डॉ. ध्रुबज्योति भट्टाचार्जी विश्व मामलों की भारतीय परिषद, नई दिल्ली में अनुसंधान अध्येता हैं।

समाप्ति नोट

[1] "चीनी प्रधानमंत्री पाकिस्तान के साथ दोस्ती में और अधिक लाभ की आशा रखते हैं" (2013), झिन्हुआनेट, *24 मई, 2015 ttp://news.xinhuanet.com/english/china/2013-05/24/c_124755924.htm*

[2] सईद शाह, "चीन के शी जिनपिंग ने पाकिस्तान में निवेश सौदे की शुरूआत की", *द वाल स्ट्रीट जर्नल*, 20 अप्रैल, 2015 http://www.wsj.com/articles/chinas-xi-jinping-set-to-launch-investment-deal-in-pakistan-1429533767

[3] विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता होंग लेई का नियमित प्रेस सम्मेलन अप्रैल 20, 2015 को, चीन जनवादी गणराज्य का विदेश मामले मंत्रालय http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/t1256093.shtml

[4] सईद शाह, "चीन के शी जिनपिंग ने पाकिस्तान में निवेश सौदे की शुरूआत की", अन्यत्र वर्णित.

[5] एंड्रयू स्टीवंस (2015), "पाकिस्तान ने चीन से 46 अरब डॉलर निवेश प्राप्त किया," *सीएनएन*, मनी, 20 अप्रैल, 2015 http://money.cnn.com/2015/04/20/news/economy/pakistan-china-aid-infrastucture/

[6] सईद शाह, "चीन के शी जिनपिंग ने पाकिस्तान में निवेश सौदे की शुरूआत की", अन्यत्र वर्णित।

[7] पूर्वोक्त।

[8] "चीन और पाकिस्तान ने कुछ ऐसा किया है जो भारत को क्रोध दिलाएगा," रेडिफन्यूज, *20 अप्रैल, 2015, http://www.rediff.com/ news/ report/china-and-pakistan-just-did-something-will-anger-india/20150420.htm*

[9] एम इलियास ख़ान, "चीन के शी जिनपिंग ने पाकिस्तान के लिए 46 अरब डॉलर के सुपर हाइवे पर सहमति जताई," *बीबीसी समाचार*, एशिया, 20 अप्रैल, 2015, http://www.bbc.com/news/world-asia-32377088

[10] "शी जिनपिंग की ऐतिहासिक दौरे पर चीन, पाकिस्तान ने सीपीईसी तथा 50 अन्य सौदों पर हस्ताक्षर किए," (2015) द इकोनॉमिक टाइम्स, *20 अप्रैल, 2015, http://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/china-pakistan-ink-cpec-50-other-deals-on-* xi-jinpings-historic-visit/articleshow/46990263.cms

[11] फ्रॉस्वा गॉडमेंट, "चीन की पड़ोस नीति," *यूरोपीय विदेश संबंध परिषद*, एशिया केन्द्र, चीनी विश्लेषण, फरवरी, 2014, http://www.ecfr.eu/page/- /China_Analysis_China_s_Neighbourhood_Policy_February2014.pdf

[12] पूर्वोक्त।

13 "*deus ex machina*'' शब्द आमतौर पर संकेतक होता है जब 'एक कदाचित न सुलझी हुई समस्या अचानक और एकाएक किसी नई घटना, चरित्र, क्षमता या वस्तु के काल्पनिक और अप्रत्याशित हस्तक्षेप द्वारा हल हो जाती है।' और यह भी समझने की आवश्यकता है कि अमरीका द्वितीय विश्व युद्ध के समय से ही विश्व राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, अमरीका पर केवल चीन के परिप्रेक्ष्य में विचार करते हुए उसका '*deus ex machina*' के रूप में विश्लेषण किया गया था।

14 फ़्राँस्वा गॉडमेंट, "चीन की पड़ोस नीति", अन्यत्र वर्णित।

15 मारियाना ब्रुन्ग्स, "चीन और इसकी क्षेत्रीय भूमिका," अल्पावधि नीति सार 77, *यूरोप चीन अनुसंधान और सलाह नेटवर्क (ईसीआरएएन)*, 2010/256-524, दिसम्बर, 2013, पृ. 4, http://eeas.europa.eu/china/docs/division_ecran/ ecran_is99_paper_77_china_and_its_regional_role_marianna_brungs_e n.pdf

16 बकले, पीटर जे, एडम आर. क्रॉस, हुई तान, लियू झिन, और हिंरिच वोस्स, "चीनी बाह्य प्रत्यक्ष निवेश में ऐतिहासिक और आकस्मिक रुझान,", *प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय समीक्षा*, खंड 48, सं. 6, (2008), पीपी 715-748

17 चीन वाणिज्य इयरबुक (2012), बीजिंग: चीन वाणिज्य और व्यापार प्रेस; चीन वाणिज्य इयरबुक (2010), बीजिंग: चीन वाणिज्य और व्यापार प्रेस

18 मोर्क, रान्डेल, बर्नार्ड युंग और मिन्युआन ज़हो, "चीन के जावक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर परिप्रेक्ष्य,"*अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अध्ययन पत्रिका*, खंड 39, सं. 3 (2008), pp. 337-350; एमिली ब्रुन्जे, निकोला लेविन, मरियम पामर और एडिसन स्मिथ, "दक्षिण एशिया में चीन का उन्नत व्यापार और निवेश (बड़ी साजिश की चेतावनी (स्पॉइलर अलर्ट): यह तो अर्थव्यवस्था है)," *रॉबर्ट एम. ला फोलेत्त स्कूल ऑफ पब्लिक अफेयर्स*, विस्कोन्सिन-मेडिसन विश्वविद्यालय, अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक मामलों पर कार्यशाला, स्प्रिंग (2013), पृ. 2, https://www.lafollette.wisc.edu/images/publications/workshops/2013-China.pdf

19 एमिली ब्रुन्जे, निकोला लेविन, मरियम पामर और एडिसन स्मिथ, "दक्षिण एशिया में चीन का बढ़ता व्यापार और निवेश (बड़ी साजिश की चेतावनी (स्प्वायलर एलर्ट): "यह तो अर्थव्यवस्था है) ", *रॉबर्ट एम. ला फोलेत्त स्कूल ऑफ पब्लिक अफेयर्स*, विस्कोन्सिन-मेडिसन विश्वविद्यालय, सार्वजनिक मामलों पर कार्यशाला, स्प्रिंग (2013), पृ. 2, https://www.lafollette.wisc.edu/images/publications/workshops/2013-China.pdf

20 पूर्वोक्त।

21 हर्ष वी पंत, "भारत और चीन के बीच सीमा पर नोकझोंक/गतिरोध क्यों बढ़ रहे हैं," बीबीसी समाचार, 26 सितंबर, 2014, http://www.bbc.com/news/world-asia-india-29373304

22 शि ईन्होंग, "चीन की जटिल विदेश नीति," *यूरोपीय विदेश संबंध परिषद*, 31 मार्च, 2015, http://www.ecfr.eu/article/commentary_chinas_complicated_foreign_policy311562

23 नाहीरो कितनो और युकिनोरी हरदा, "चीन की विदेशी सहायता का आकलन 2001-2013', विकासात्मक सहयोग कार्यनीति का तुलनात्मक अध्ययन : जी 20 की उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर ध्यान केन्द्रित करना, सं. 78 (2014), *जेआईसीए अनुसंधान संस्थान*, टोक्यो, पृ. 3; "विदेशी सहायता पर चीन का दूसरा श्वेत पत्र", मुद्दा सार, *संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम*, दक्षिण दक्षिण सहयोग चीन, सं. 5 (2014), अगस्त, http://www.cn.undp.org/content/dam/china/docs/ Publications/UNDP-CH-ISSUE%20BRIEF.pdf

24 इशान थरुर, "चीन और पाकिस्तान की खास दोस्ती के मायने क्या हैं," *द वॉशिंगटन पोस्ट*, 21 अप्रैल, 2015, http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2015/04/21/what-china-and-pakistans-special-friendship-means/

25 सलमान मसूद और डक्लन वाल्श, "शी जिनपिंग ने पाकिस्तान को धन मुहैया कराने की योजना बनाई," द न्यूयॉर्क टाइम्स, 21 अप्रैल, 2015, http://www.nytimes.com/2015/04/22/world/asia/xi-jinping-plans-to-fund-pakistan.html?_r=0

[26] सउद मेहसुद और मारिया गोलोव्नीना, "पाकिस्तान में अपने छिपने के ठिकाने से उइघुर नेता ने चीन से बदला लेने की प्रतिज्ञा की," मार्च 14, 2014, *रायटर*, http://www.reuters.com/article/2014/03/14/us-pakistan-uighurs-idUSBREA2D0PF20140314

[27] एम इलियास ख़ान, "चीन के शी जिनपिंग ने पाकिस्तान के लिए 46 अरब डॉलर के सुपर हाइवे पर सहमति जताई," *बीबीसी समाचार*, एशिया, 20 अप्रैल, 2015, http://www.bbc.com/news/world-asia-32377088

[28] "शी के दौरे की समाप्ति पर चीन-पाकिस्तान कॉरिडोर/गलियारे के लिए सुरक्षा का डर, *डेली मेल*, मेल ऑनलाइन, 21 अप्रैल, 2015, http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-3048553/Security-fears-China-Pakistan-corridor-Xi-ends-visit.html ,

[29] बाक़ीर सज्जाद सैयद, "गलियारा परियोजनाओं की सुरक्षा के लिए विशेष सैन्यबल", *डॉन*, 21 अप्रैल, 2015, http://www.dawn.com/news/1177491/special-force-to-protect-corridor-projects

[30] एम इलियास ख़ान, "चीन के शी जिनपिंग ने पाकिस्तान के लिए 46 अरब डॉलर के सुपर हाइवे पर सहमति जताई," ओपी. सीआईटी.

[31] एंड्रयू स्टीवेंस, "पाकिस्तान ने चीन से 46 अरब डॉलर निवेश प्राप्त किया", अन्यत्र वर्णित।

[32] ग्राहम टी. एलीसन, "ओबामा और शी को क्लासिक/परंपरागत फंदे से बचने के लिए व्यापक और खुलकर सोचना होगा," *न्यूयॉर्क टाइम्स*, 6 जून, 2013, http://www.nytimes.com/2013/06/07/opinion/obama-and-xi-must-think-broadly-to-avoid-a-classic-trap.html?_r=0

[33] फ़्राँस्वा गॉडमेंट, "चीन की विदेश नीति के पुनर्निर्धारण की व्याख्या," *यूरोपीय विदेश संबंध परिषद*, एशिया केन्द्र, चीनी विश्लेषण, अप्रैल (2015), विशेषांक, पीपी 2-3

[34] फ़्राँस्वा गॉडमेंट, "चीन की पड़ोस नीति," *यूरोपीय विदेश संबंध परिषद*, एशिया केन्द्र, चीनी विश्लेषण, फरवरी (2014), http://www.ecfr.eu/page/- /China_Analysis_China_s_Neighbourhood_Policy_February2014.pdf

[35] शान्नोन तिएज़्ज़ी, "चीन क्यों नरेंद्र मोदी को दुविधा में डालता है," *द डिप्लोमैट*, 29 मई, 2014 http://thediplomat.com/2014/05/why-china-embraces-narendra-modi/

[36] फ़्राँस्वा गॉडमेंट (2015), "चीन की विदेश नीति के पुनर्निर्धारण की व्याख्या," अन्यत्र वर्णित।

[37] सलमान मसूद और डाल्कन वॉल्श, " शी जिनपिंग ने पाकिस्तान को धन मुहैया कराने की योजना बनाई," अन्यत्र वर्णित।

[38] इशान थरुर, "चीन और पाकिस्तान की खास दोस्ती का मतलब क्या है," अन्यत्र वर्णित।

[39] खालिक़ कियानी (2015), "फास्ट ट्रैक परियोजनाओं के लिए 28 अरब डॉलर का समझौता," डॉन, *21 अप्रैल, 2015 http://www.dawn.com/news/1177233/28bn-accords-for-fast-track-projects*

[40] पूर्वोक्त।

[41] पूर्वोक्त।

[42] पूर्वोक्त।

[43] पूर्वोक्त।

[44] पूर्वोक्त।

[45] "चीनी राष्ट्रपति शी पाकिस्तान में 46 अरब डॉलर लगाने के लिए कदम उठा रहे हैं," *बिजनेस इनसाइडर*, 20 अप्रैल, 2015, http://www.pcgv.org/April%2020%202015.pdf

[46] मिंक्सिन पेई, "क्यों चीन खरबों का निवेश बेकार करता जा रहा है," *फार्चून*, 1 दिसंबर, 2014, http://fortune.com/2014/12/01/china-investment-losses-infrastructure/

[47] पूर्वोक्त।

[48] जांग चुन (2014), "क्यों किसी को प्रवासी चीनी कंपनियां पसंद नहीं?" *चाइना डायलॉग*, 12 सितम्बर, 2015 ttps://www.chinadialogue.net/article/show/single/en/7299-Why-does-no-one-like-Chinese-companies-overseas-

[49] पूर्वोक्त।

[50] अनुसंधान अध्येताओं के साथ नागेन्द्र कु. सक्सेना, उप महानिदेशक, विश्व मामलों की भारतीय परिषद की चर्चा, 28 अप्रैल 2015

[51] निकलस नोर्लिंग, "उभरता चीन-अफगानिस्तान संबंध," *मध्य एशिया-काकेशस संस्थान विश्लेषक*, 14 मई, 2008, http://www.cacianalyst.org/?q=node/4858/print

[52] चार्ल्स वालेस, "अमरीका नहीं, चीन को अफगानिस्तान के खनिज संपदा से लाभ होने की संभावना," *डेली फाइनॉंस* 14 जून, 2010, http://www.dailyfinance.com/2010/06/14/china-us-afghanistan-mineral-mining

[53] जैसन हींग, "वर्ष 2013 में चीनी साम्राज्यवाद: अप्रतिबंधित वारफेयर के अनुप्रयोग या राष्ट्रीय शक्ति के आर्थिक साधनों का वैध उपयोग?" *विदेशी सैन्य अध्ययन कार्यालय (एफएमएसओ)*, (2014), फोर्ट लेआवेनवर्थ, संयुक्त राज्य अमेरिका, http://fmso.leavenworth.army.mil/Collaboration/Interagency/chinese-imperialism.pdf

[54] आमिर मीर, "चीन चाहता है पाकिस्तान में सैन्य अड्डे," *साउथ एशिया टाइम्स*, 26 अक्टूबर, 2011 http://www.atimes.com/atimes/South_Asia/MJ26Df03.html

[55] मोनिका चन्सोरिया, "चीन ने पाक अधिकृत कश्मीर में अपनी उपस्थिति का एहसास कराया," *द संडे गार्जियन*, 27 अप्रैल, 2015, http://www.sunday-guardian.com/analysis/china-makes-its-presence-felt-in-pak-occupied-kashmir

[56] "भारत को चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के विरोध में जोरदार आवाज उठानी चाहिए," *बिजनेस स्टैंडर्ड*, 21 अप्रैल, 2015, http://www.business-standard.com/article/news-ians/india-should-be-upfront-in-voicing-opposition-to-china-pakistan-economic-corridor-115042100473_1.html

[57] ब्रिगे. विनोद आनंद, "चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा: संभावनाएं और मुद्दे," *विवेकानन्द इंटरनेशनल फाउंडेशन*, 8 अप्रैल, 2015, www.vifindia.org/print/2481

[58] "विवादित अरुणाचल प्रदेश के मोदी के दौरे पर चीन ने विरोध जताया," (2015) रायटर, *21 फ़रवरी, 2015, http://in.reuters.com/article/2015/02/21/china-india-territory-idINKBN0LO1LA20150221*

[59] दीपांजन रॉय चौधरी, "भारत ने चीन की महत्वाकांक्षा के जवाब में कपास, प्राचीन समुद्री मार्गों की योजना बनाई," *इकोनॉमिक टाइम्स*, 17 अप्रैल, 2015, http://articles.economictimes.indiatimes.com/2015-04-17/news/61253559_1_maritime-silk-road- indian-ocean-chinese-silk

[60] "यह ईरानी पत्तन क्यों है महत्वपूर्ण," *द इकोनॉमिक टाइम्स*, 23 अक्तूबर 2014 http://articles.economictimes.indiatimes.com/2014-10-23/news/55358943_1_gwadar-chabahar-port-chahbahar